

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1]
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts

New Delhi, the 18th day of August, 2025

Resolution

Subject: Rationalization of Domestic Mail Products and Services

The Government of India has undertaken an exercise to rationalise the suite of postal products & services offered by the Department of Posts. As part of this exercise, keeping in view necessary legal requirements with respect to delivery of summons, notices, and other statutory documents, it is hereby notified that, Registration, a value-added service, will now be available under the following revised framework, within the country.

- (a) Speed Post, i.e., Speed Post Letter and Speed Post Parcel, shall henceforth be the basic mail service for address-specific delivery of accountable postal items in the country; and
 - (b) Registration will be available as a value-added service for Speed Post items only and shall provide addressee-specific delivery. Registration will not be available for other categories of mail.
2. This revised framework is in line with the Government's commitment to better align these services with evolving market demands and customer expectations.
 3. The operational guidelines, applicable tariffs and service terms for Speed Post and value-added services including Registration, shall be as notified by the Department from time to time.
 4. The above will come into effect from 01.10.2025.

[No. Mail-30/5/2025-D-DOP]



(Dushyant Mudgal)
Deputy Director General

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to Statutory Bodies, Constitutional Bodies, to all Ministries/Departments of the Govt. of India, all State Governments and Union Territories, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, the Registrar General of Supreme Court of India etc.

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.


(Dushyant Mudgal)
Deputy Director General

The Manager,
Government of India Press,
(Bharat Sarkar Press)
Faridabad

Copy forwarded to:

1. PS to Hon'ble Minister of Communications/PS to Hon'ble Minister of State for Communications.
2. PPS to Secretary (Posts)/PPS to Director General Postal Services.
3. PPS/PS to All Members of Postal Services Board.
4. All concerned Ministries/Department & Stakeholders.
5. AS&FA/ Sr. DDG (PAF)/ Sr. DDG (Vigilance) & CVO/ MD&CEO. IPPB /Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad.
6. All Chief Postmasters General/ CGM (PLI) & CGM (Parcel).
7. Secretary (PSB)/All Postmasters General/ All DDsG/GMs (PLI, BD & Parcel Dte), /Addl. DG, APS, C/o 56 APO.
8. GM (CEPT), Mysore, with a request to upload the order in India Post Website.
9. All General Managers (Finance)/Directors Postal Accounts/DDAP.
10. Chief Engineer (Civil/Electrical), Director MV, Postal Directorate.
11. All Directors, Postal Training Centres.
12. Director (Admn.), Dak Bhawan, New Delhi.
13. ADsG (Admn.)/(Gen. Admn.).
14. All Sections of Postal Directorate (through e-Office).
15. EA/C&A/PB/Admn./CA/PE-II/Parliament Sections & NIC, Dak Bhawan.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग**

नई दिल्ली, वर्ष 2025 के अगस्त माह का 18वाँ दिन

संकल्प

विषय : घरेलू डाक उत्पादों और सेवाओं का युक्तिकरण

भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक सेवाओं और उत्पादों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है। इसके एक भाग के रूप में; समन, नोटिस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के वितरण से संबंधित आवश्यक विधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित किया जाता है कि पंजीकरण, जो एक मूल्यवर्धित सेवा है, अब देश में निम्नलिखित संशोधित फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध होगी।

(क) अब से, स्पीड पोस्ट अर्थात् स्पीड पोस्ट लेटर और स्पीड पोस्ट पार्सल को देश में जवाबदेह डाक वस्तुओं के पता-विशिष्ट वितरण के लिए मौलिक डाक सेवा माना जाएगा; और

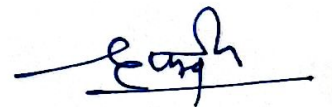
(ख) पंजीकरण, केवल स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए मूल्यवर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध होगा और इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता-विशिष्ट वितरण प्रदान किया जाएगा। अन्य श्रेणियों की 'डाक' के लिए पंजीकरण उपलब्ध नहीं होगा।

2. यह संशोधित फ्रेमवर्क, इन सेवाओं को 'बाजार की निरंतर बदलती मांगों' और 'ग्राहकों की अपेक्षाओं' के अनुरूप बेहतर बनाने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है।

3. स्पीड पोस्ट और, पंजीकरण सहित मूल्यवर्धित अन्य सेवाओं संबंधी प्रचालन दिशानिर्देश, लागू टैरिफ और सेवा शर्तें, विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

4. उपर्युक्त संकल्प दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा।

[सं. मेल-30/5/2025-डी-डीओपी]



**(दुष्यंत मुद्गल)
उप महानिदेशक**

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सांविधिक निकायों, संवैधानिक निकायों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महापंजीयक आदि को प्रेषित की जाए।
आदेश है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।


(दुष्यंत मुद्गल)
उप महानिदेशक

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद

प्रतिलिपि प्रेषित : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265516
CG-DL-E-19082025-265516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2025

विषय : घरेलू डाक उत्पादों और सेवाओं का युक्तिकरण

फा. सं. मेल-30/5/2025-डी-डीओपी.—भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक सेवाओं और उत्पादों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है। इसके एक भाग के रूप में; समन, नोटिस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के वितरण से संबंधित आवश्यक विधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित किया जाता है कि पंजीकरण, जो एक मूल्यवर्धित सेवा है, अब देश में निम्नलिखित संशोधित फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध होगी।

- (क) अब से, स्पीड पोस्ट अर्थात् स्पीड पोस्ट लेटर और स्पीड पोस्ट पार्सल को देश में जवाबदेह डाक वस्तुओं के पता-विशिष्ट वितरण के लिए मौलिक डाक सेवा माना जाएगा; और
- (ख) पंजीकरण, केवल स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए मूल्यवर्धित सेवा के रूप में उपलब्ध होगा और इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता-विशिष्ट वितरण प्रदान किया जाएगा। अन्य श्रेणियों की 'डाक' के लिए पंजीकरण उपलब्ध नहीं होगा।

2. यह संशोधित फ्रेमवर्क, इन सेवाओं को 'बाजार की निरंतर बदलती मांगों' और 'ग्राहकों की अपेक्षाओं' के अनुरूप बेहतर बनाने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है।

3. स्पीड पोस्ट और, पंजीकरण सहित मूल्यवर्धित अन्य सेवाओं संबंधी प्रचालन दिशानिर्देश, लागू टैरिफ और सेवा शर्तें, विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

4. उपर्युक्त संकल्प दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा।

दुष्यंत मुद्गल, उप महानिदेशक

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सांविधिक निकायों, संवैधानिक निकायों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महापंजीयक आदि को प्रेषित की जाए।

आदेश है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दुष्यंत मुद्गल, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th August, 2025

Subject: Rationalization of Domestic Mail Products and Services

F. No. Mail-30/5/2025-D-DOP.—The Government of India has undertaken an exercise to rationalise the suite of postal products & services offered by the Department of Posts. As part of this exercise, keeping in view necessary legal requirements with respect to delivery of summons, notices, and other statutory documents, it is hereby notified that, Registration, a value-added service, will now be available under the following revised framework, within the country.

- (a) Speed Post, i.e., Speed Post Letter and Speed Post Parcel, shall henceforth be the basic mail service for address-specific delivery of accountable postal items in the country; and
 - (b) Registration will be available as a value-added service for Speed Post items only and shall provide addressee-specific delivery. Registration will not be available for other categories of mail.
2. This revised framework is in line with the Government's commitment to better align these services with evolving market demands and customer expectations.
 3. The operational guidelines, applicable tariffs and service terms for Speed Post and value-added services including Registration, shall be as notified by the Department from time to time.
 4. The above will come into effect from 01.10.2025.

DUSHYANT MUDGAL, Dy. Director General

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to Statutory Bodies, Constitutional Bodies, to all Ministries/Departments of the Govt. of India, all State Governments and Union Territories, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, the Registrar General of Supreme Court of India etc.

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

DUSHYANT MUDGAL, Dy. Director General